	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गांवों की कुल संख्या	सड़कों से जुड़े गांव	सड़कों से न जुड़े गांव	सड़कों से जुड़े गांवों का प्रतिशत	सड़कों से न जुड़े गांवों का प्रतिशत
27.	मणिपुर	2037	955	1082	46.88	53.12
28.	मेघालय	737	629	108	85.35	52.06
29.	मिजोरम	737	629	108	85.35	14.65
30.	नागालैण्ड	1119	964	155	86.15	13.85
31.	सिक्किम	440	295	145	67.05	32.95
32.	त्रिपुरा	4718	3590	1128	76.09	23.91
	कुल	39706	24543	15163	61.81	38.49
	कुल—भारत	589117	274088	315029	46.52	53.48

भूतल परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 1996-97 में प्रकाशित बेसिक रोड स्टेटिस्टिक्स आफ इंडिया पर आधारित।

All Weather Roads in Villages

†*142 SHRI RAJ MOHINDER SINGH:@
SHRI RAJIV RANJAN SINGH:

Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that more than fifty percent of villages in the country are not connected with perennial roads;

(b) if so, the actual number of villages connected with perennial roads;

(c) whether any assessment has since been made regarding the connectivity of villages with perennial roads in the country; and

(d) if so, the percentage of the villages connected with perennial roads in Bihar, Uttar Pradesh, Rajasthan, Haryana and Punjab, separately?

THE MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI SUNDERLAL PATWA): (a) to (d) A statement is laid on the table of the House.

†Original notice of the question was received in Hindi.
@The question was actually asked on the floor of the House by Shri Raj Mohinder Singh.

Statement

Information in respect of the number of villages connected in different States/Union Territories as on 31st March, 1992 is given in the annexed table (*see* below). The Planning Commission have estimated that as on 31.3.1997, 3,53,287 out of 6,24,723 villages were connected.

Subsequently, an assessment in regard to the connectivity of villages through All-weather roads has also been initiated, in the light of which, a National Rural Roads Programme (NRRP) is being formulated.

Table

The Status of Rural Connectivity in Different States/UTs (1991-92)

	State/UT	Total No. of Vilage	Villages Connected	Villages Un-connected	% of villages having connec-tivity	% of villages lacking connec-tivity
1	Andhra Pradesh	27355	15927	11428	58.22	41.78
2	Bihar	67566	22894	44672	33.88	66.12
3	Goa	398	373	25	93.72	6.28
4	Gujarat	18114	15445	2669	85.27	14.73
5	Haryana	6745	6677	68	98.99	1.01
6.	Himachal Pradesh	16807	7498	9309	44.61	55.39
7	Jammu & Kashmir	6215	3844	2371	61.85	38.15
8	Karnataka	27028	12894	14134	47.71	52.29
9	Kerala	1268	1268	0	100.00	0.00
10	Madhya Pradesh	70883	19504	51379	27.52	72.48
11	Maharashtra	36385	17104	19281	47.01	52.99
12	Orissa	47305	16874	30341	35.67	64.22
13.	Punjab	12188	12075	113	99.07	0.93
14	Rajasthan	33305	11436	21869	34.34	65.66
15	Tamil Nadu	26099	18089	8010	69.31	30.69
16.	Uttar Pradesh	112566	49268	63298	43.77	56.23
17	West Bengal	38074	17506	20568	45.98	54.02
18	A&N Islands	491	254	237	51.73	48.27
19	D&N Haveli	72	68	4	94.44	5.56
20	Daman & Diu	26	26	0	100.00	0.00
21	Lakshadweep				0.00	0.00
22	Pondicherry	291	291	0	100.00	0.00

	State/UT	Total No. of Vilage	Villages Connected	Villages Un-connected	% of villages having connec-tivity	% of villages lacking connec-tivity
23.	Delhi	214	214	0	100.00	0.00
24.	Chandigarh	16	16	0	100.00	0.00
	Total	549411	249545	299866	45.42	54.58
North Eastern States						
25.	Arunachal Pr.	3257	679	2578	20.85	79.15
26.	Assam	22496	15081	7415	67.04	32.96
27.	Manipur	2037	955	1082	46 .88	53.12
28.	Meghalaya	4902	2350	2552	47.94	52.06
29.	Mizoram	737	629	108	85.35	14.65
30.	Nagaland	1119	964	155	86.15	13.85
31.	Sikkim	440	295	145	67.05	32.95
32.	Tripura	4718	3590	1128	76.09	23.91
	Total	39706	24543	15163	61.81	38.19
	Total—India	589117	274088	315029	46.52	53.48

Based on Basic Road Statistics of India published in 1996-97 by the Ministry of Surface Transport. Government of India.

श्री राज मोहिन्दर सिंह: चेयरमैन साहब, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इन्होंने स्वयं अपने उत्तर में 50 परसेंट की फिगर दी है यानी वे स्वयं मानते हैं कि 50 परसेंट गांव अभी सड़कों से जुड़े हुए नहीं हैं। महोदय, हमारे देश में कई राज्य ऐसे हैं जहां ऐसे गांवों की संख्या 70 प्रतिशत तक है जिनके अभी सड़कें नहीं मिली हैं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या वे कोई टाईम बाऊंड प्रोग्राम बनाएंगे ताकि अभी तक जो मध्य प्रदेश में 72 प्रतिशत, राजस्थान में 65 प्रतिशत और अरुणाचल प्रदेश में 80 प्रतिशत गांवों को सड़कें नहीं मिली हैं, उनको ये सड़कें मिल सकें? महोदय, अखबारों में रोज आता है कि हम हर गांव को सड़क से जोड़ेंगे। अभी भी हमारे कई राज्यों में ऐसे गांव हैं, जहां पर कोई सड़क नहीं जाती। मैं मिनस्टिर साहब से पूछना चाहूंगा कि क्या वे कोई ऐसा टाईम बाऊंड प्रोग्राम बनाएंगे ताकि सभी गांवों को सड़क मिल सके?

श्री सुन्दर लाल पटवा: सभापति महोदय, मुझे सदन को यह बताते हुए तसल्ली है कि पहली बार देश में वर्तमान सरकार और उसके प्रधान मंत्री जी ने यह निश्चय किया कि देश के हरेक गांव को सड़क से जोड़ा जाए और उन्होंने इसकी घोषणा भी की है और इसके लिए प्रबंध भी किया है। हम एक टाईम बाऊंड प्रोग्राम के अंतर्गत देश के सभी गांवों को सड़कों से जोड़ देंगे। इसलिए एक विशेष कर सैस के रूप में लगाया गया है। उसके बाद एक कमेटी इस बारे में बनाई गई थी। उस कमेटी की रिपोर्ट आ गई है और उस पर आगे कार्यवाही चल रही है। मुझे विश्वास है कि जल्दी ही हम कैबिनेट की सैंक्शन के बाद इस सदन में इस बारे में ऐनाउंसमेंट करेंगे। सरकार का निश्चय है कि सभी गांवों को सड़कों से जोड़ा जाए।

सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने संख्या के बारे में पूछा था तो उत्तर में जो संख्या बताई गई वह 1992 के सर्वे के आधार पर बताई गई है और योजना आयोग ने 1997 में जो अनुमान लगाया था, उसके आंकड़े दिए गए हैं। उसमें भी मैं यह स्वीकार करने के लिए तैयार हूं कि जो सड़कें बनी हुई बताई गई हैं, उनमें से सभी को बारहमासी कहना ठीक नहीं है। इनमें से बहुत सी सड़कों को ठीक करने की जरूरत है। इस कार्य को हम एक टाईम बाऊंड प्रोग्राम के अंतर्गत लेकर पूरा करेंगे।

श्री राज मोहिन्दर सिंह: सभापति महोदय, पिछले साल पेट्रोल और डीज़ल पर टैक्स लगाकर रोड़ फंड इकट्ठा किया गया और उसमें करीब 2,500 करोड़ रुपया आया। महोदय, आज भी भारत की 75 प्रतिशत पापुलेशन गांवों में रहती है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि 2,500 करोड़ रुपये से कुछ नहीं होने वाला है। इसके लिए कुछ और फंड्ज़ मुहैया किए जाएं ताकि आने वाले सालों में हमारे मुल्क के हर गांव को सड़क मिल सके।

श्री सुन्दर लाल पटवा: सभापति महोदय, माननीय सदस्य का कहना सही है कि अगर केवल 2,500 करोड़ रुपये से हम इस कार्यक्रम को चलाएं तो वर्तमान स्थिति में सभी गांवों को जोड़ने के लिए करीब 30 साल का समय लगेगा। इसलिए यह प्रयास किया जा रहा है कि इस काम को संक्षिप्त समय में पूरा किया जाए। हमने जो कमेटी इस बारे में बनाई थी, उसकी रिपोर्ट आ गई है। उसमें कुछ सुझाव दिए गए हैं और उन पर कार्यवाही की जा रही है। उस कार्यवाही के पूरा होने तक मैं माननीय सदस्य से इंतज़ार करने का आग्रह करूंगा।

श्री राजीव रंजन सिंह: सभापति महोदय, मंत्री जी ने अपने उत्तर में जो राज्यवार विवरण दिया है, वह भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा 1996-97 में प्रकाशित बेसिक रोड़ स्टेटिस्टिक्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पर आधारित है। उसकी ताजा रिपोर्ट जो इंडिया ह्यूमन डेवलपेंट रिपोर्ट 1999 के आधार पर समाचारपत्रों में छपी है, उसके अनुसार पक्की सड़कों से जुड़े गांवों का राष्ट्रीय औसत 36.8 परसेंट है। और इसमें बिहार का औसत है 19 प्रतिशत। तो हम सरकार से यह जानना चाहते हैं कि बिहार का औसत राष्ट्रीय औसत से लगभग आधे के बराबर होने का क्या कारण है और राष्ट्रीय औसत के अनुरूप इसे लाने के लिए और जो नया एन॰ आर॰ आर॰ पी॰ प्रोग्राम है इसके कार्यान्वयन में कारगर नियंत्रण के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है?

श्री सुन्दर लाल पटवा: सभापति महोदय, सड़कों का औसत केवल बिहार में कम है, ऐसा नहीं है। आधा दर्जन से ज्यादा प्रदेश ऐसे हैं जिसमें सड़कों का प्रतिशत 30 से भी नीचे है और इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसा कोई प्रोग्राम-फ्रेमवर्क करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि जो यह इमबेलेंस है इसको भी ध्यान में रखते हुए सब प्रदेशों को एक साथ समान स्तर पर लाया जा सके और उसके लिए कार्रवाई जारी है।

श्री राजीव रंजन सिंह: महोदय, मैंने सरकार से जानना चाहा था कि इसके कार्यान्वयन पर कारगर नियंत्रण के लिए भारत सरकार क्या कोई कार्रवाई करने जा रही है?

श्री सुन्दर लाल पटवा: सभापति महोदय, हम सभी चाहते हैं कि जो पैसा जिस काम पर खर्च होने के लिए तय किया जाता है उस काम पर पूरा-पूरा खर्च हो और उसका लाभ जनता को मिले। परन्तु वस्तु-स्थिति यह है कि सड़क राज्यों का विषय है। हमारा रोल राज्यों के एक सहायक और सहयोग और सहयोगी के रूप में है। हम कोशिश करते हैं राज्य सरकारों को सहायता करने की और उस नियंत्रण में भी अगर हमारे पास कोई शिकायत आती है, कोई जानकारी आती है तो राज्य सरकारों को उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए कहते हैं। परन्तु जैसी संवैधानिक स्थिति है उसमें केन्द्र सरकार सीधे कार्रवाई करे, यह संभव नहीं है। राज्य सरकारों पर भरोसा करके चलाना पड़ता है।

DR. MANMOHAN SINGH: Mr. Chairman, Sir, the figures supplied by the hon. Minister relate to the year 1991-92. Obviously, these figures are nearly ten years old and, therefore, they can hardly form the basis of any intelligent planning of the Rural Roads Programme. The Government have now imposed a cess on petroleum products and according to the declared policy of the Government, a specific part of that money is going to be used for the Rural Roads Programme. But, if the Government have no clear idea of where there is an unfulfilled need, how are they going to spend that money?

श्री सुन्दर लाल पटवा: श्रीमन्, जो आंकड़े मैंने बताए हैं उसके अलावा भी जो कमेटी हमने बनाई थी उस कमेटी ने राज्य सरकारों से अद्यतन जानकारी, लेटेस्ट इंफार्मेशन प्राप्त करने की कोशिश की है और राज्य सरकारों ने जो लेटेस्ट इंफार्मेशन हमको दी है उसके आधार पर हम जो भी प्रोग्राम बनाएंगे उसमें कोशिश यह होगी कि सभी गांवों को बारहमासी पक्की डांवर से बनाई हुई सड़कें उपलब्ध हों, यह हमारी कोशिश होगी। अच्छी क्वालिटी की रोड़ बनें। There will be no compromise on the quality.

श्री गांधी आज़ाद: धन्यवाद महोदय, ग्रामों को जोड़ने के लिए डा० अम्बेडकर ग्राम योजना, स्वराज ग्राम योजना, गांधी ग्राम योजना खास तौर से उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि पिछले तीन वर्षों में इस योजना द्वारा कितने गांवों को जोड़ा गया है और अगले तीन वर्षों में कितने गांवों को जोड़ने की योजना है?

श्री सुन्दर लाल पटवा: इसके लिए अलग से सूचना अगर माननीय सदस्य दें तो मैं राज्य सरकार से जानकारी लेकर उनको उपलब्ध करवा दूंगा।

सरदार बलविन्दर सिंह भुंडर: ऑनरेबिल चेयरमैन साहब, जो एन० आर० आर० पी० फंड किया गया स्पेशल सेस् लगा करके, उसके लिए कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है और जो ये फिगर्स आई हैं कि किसी स्टेट में 30 परसेंट हैं, किसी में 50 परसेंट हैं, तीन स्टेट में-केरल, पंजाब और

हरियाणा, जहां 98, 99 और 100 परसेंट सड़कें लिंक रोड़ बन गई हैं, तो मंत्री महोदय से मैं स्पेशली यह जानना चाहता हूं कि क्या यह फंड स्पेशली सेस् लाकर क्रिएट किया गया है? यह जो फंड है उसमें जिस स्टेट से जितना सेस् कलेक्ट किया गया क्या उसके मुताबिक स्टेट की रोड़ रिपेयर के लिए भी देंगे? कहीं यह तो नहीं हो जाएगा कि जहां स्टेट ने पहले काम कर लिया वह स्टेट तो खत्म हो गया इसलिए.....

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Discussion on Indo-Nepal Security Issues

*143. SHRI PARMESHWAR KUMAR AGARWALLA: Will the Minister of HOME AFFARIS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that discussions were held recently between India and Nepal on security related matters;

(b) if so, what are the main issues discussed; and

(c) what is the outcome thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI I.D. SWAMI): (a) and (b) Home Secretary level talks were held in Kathmandu from July 4.7.2000. At this meeting the two sides discussed modalities to enhance cooperation in combating activities of terrorist, criminal and other undersirable elements, including along the India-Nepal border. Cooperation between the law enforcement agencies of both the countries and improved management of the India-Nepal border were also discussed.

(c) it was agreed to further intensify cooperation and jointly coordinate measures, including stepping up vigil along the contiguous border districts of India and Nepal, to counter activities inimical to India's interests. Shared concern on this matter was evident from the determination expressed by both sides to take urgent necessary steps to control misuse of the open border between the two countries. It was also agreed to introduce with effect from October 1,2000, a "pruned down" list of photo identification documents that would be valid for air travel by India and Nepalese nationals between the two countries.